51 .5 लाख सिलेंडर हुए वितरित

मौजूदा परिस्थितियों के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी उपलब्ध

डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग करें

नई दिल्ली, 12 अप्रैल पश्चिम एशिया में बदलते भू-राजनीतिक हालात और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बनी अनिश्चितताओं के बीच भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और सक्रिय कदम उठाए हैं.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा परिस्थितियों के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति को लेकर किसी भी प्रकार की कमी या बाधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है. मंत्रालय ने कहा है कि देशभर में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी और समन्वय किया जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित संकट की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और देश के किसी भी हिस्से से आपूर्ति बाधित होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है. इसके साथ ही उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक उपयोग करें.

> इसके अलावा सरकार ने एलपीजी की मांग को संतुलित करने के लिए वैकल्पिक ईंधन स्रोतों को भी बढ़ावा दिया है. केरोसिन, कोयला और अन्य विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों को सक्रिय किया गया है. कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगारेनी कोलियरीज को निर्देश दिए हैं कि वे राज्यों को अतिरिक्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करें.

कोल इंडिया लिमिटेड ने बढ़ती लागत खुद उठाने का फैसला किया

नई दिल्ली, 12 अप्रैल. देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी (कोल इंडिया लिमिटेड)(सीआईएल) ने एक अहम निर्णय लेते हुए बढ़ती उत्पादन लागत का बोझ खुद उठाने का फैसला किया है. कंपनी ने साफ किया है कि वह कोयले की कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी, ताकि बिजली और अन्य जरूरी क्षेत्रों में महंगाई का दबाव न बढ़े. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ईंधन और विस्फोटक सामग्री की लागत में भारी उछाल आया है. देश में ऊर्जा लागत को नियंत्रित रखने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए (कोल इंडिया लिमिटेड) (सीआईएल) ने यह घोषणा की है कि वह बढ़ती उत्पादन लागत का बोझ खुद वहन करेगी.

एफपीआई निकासी से शेयर बाजार में गिरावट

विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर और डेट बाजार से पूंजी निकाली

मुंबई, 12 अप्रैल: भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली का दबाव लगातार बना हुआ है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल महीने में अब तक एफपीआई ने भारतीय बाजार से कुल 62,204 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की है. यह रुझान इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं, विशेषकर पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव, ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया है.

केंद्रीय डिपॉजिटरी सेवा (सीडीएसएल) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल में एफपीआई ने सबसे अधिक निकासी इक्विटी बाजार से की है. इस दौरान उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से 48,213 करोड़ रुपये की पूंजी बाहर निकाली. इसका सीधा असर बाजार की धारणा और अस्थिरता पर देखने को मिल रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक जोखिम से बचाव की रणनीति के तहत विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से पूंजी निकालकर सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं.

सिर्फ इक्विटी ही नहीं, बल्कि डेट और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में भी एफपीआई का रुख नकारात्मक रहा है. अप्रैल में अब तक डेट मार्केट से 14,106 करोड़ रुपये की निकासी हुई है, जबकि हाइब्रिड उपकरणों में भी 44.42 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली दर्ज की गई है.

> मार्च महीने में भी एफपीआई ने भारतीय बाजार से भारी बिकवाली की थी, जब उन्होंने रिकॉर्ड 1,26,991 करोड़ रुपये की निकासी की थी. इससे पहले फरवरी में स्थिति कुछ बेहतर थी, जब विदेशी निवेशकों ने 37,847 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था. लेकिन मौजूदा कैलेंडर वर्ष के कुल आंकड़े बताते हैं कि अब तक एफपीआई ने कुल 1,80,419 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी कर ली है, जो बाजार के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है.

चावल, गेहूं में साप्ताहिक गिरावट

चीनी मजबूत; खाद्य तेल, दालों में घट-बढ़

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल के औसत भाव गिर गये. गेहूं में भी नरमी रही. चीनी में मजबूती देखी गयी जबकि दालों और खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा.

सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 67 रुपये टूटकर सप्ताहांत पर 3,759 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी. गेहूं 14 रुपये गिरकर 2,770 रुपये प्रति क्विंटल बोला गया. आटा 15 रुपये महंगा हुआ और 3,278 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया.

सप्ताह के दौरान उड़द दाल की औसत कीमत 28 रुपये और मूंग दाल की सात रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी. मसूर दाल 43 रुपये सस्ती हुई. तुअर दाल और चना दाल की कीमत 13-13 रुपये प्रति क्विंटल टूट गयी.

बीते सप्ताह मूंगफली तेल औसतन 207 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ. सोया तेल की कीमत 125 रुपये और पाम ऑयल की 112 रुपये बढ़ गयी. सूरजमुखी तेल में 94 रुपये और सरसों तेल में 31 रुपये की मजबूती देखी गयी. वनस्पति पांच रुपये प्रति क्विंटल सस्ता हुआ.

मीठे के बाजार में बीते सप्ताह गुड़ का औसत भाव सात रुपये प्रति क्विंटल टूट गया. वहीं, चीनी भी 23 रुपये महंगी हुई.

एआई प्लस स्मार्टफोन ने नोवा सीरीज़ लॉन्च की

कस्टमाइज़ेबल टेक्नोलॉजी के साथ टैबलेट और वेयरेबल्स में किया पेश

नई दिल्ली. एआई प्लस स्मार्टफोन ने लॉन्च की अपनी महत्वाकांक्षी नोवा सीरीज़'; टैबलेट और वेयरेबल्स के साथ पेश किया अपना पहला कनेक्टेड इकोसिस्टम नोवा 2, नोवा 2 अल्ट्रा और नोवा फ्लिप के लॉन्च के साथ, एआई प्लस स्मार्टफोन्स ने अब तक का सबसे बड़ा रणनीतिक विस्तार किया है.

कंपनी अब केवल एक स्मार्टफोन ब्रांड तक सीमित न रहकर, एक पूर्ण 'कनेक्टेड इकोसिस्टम' प्लेयर बनने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा रही है. स्मार्टफोन बाज़ार में अपनी पकड़ मज़बूत करने के साथ ही, कंपनी ने अपना पहला टैबलेट, नये ऑडियो प्रोडक्ट्स और

वियरेबल्स की एक विस्तृत रेंज भी लॉन्च की है. यह पूरा पोर्टफोलियो सरलता, प्राइवेसी और रोज़मर्रा की ज़रूरत पर केंद्रित है, जो एक सहज 'कनेक्टेड इकोसिस्टम' को साकार करता है.

इस सीरीज़ के केंद्र में तीन खास 5 जी स्मार्टफोन- नोवा 2, नोवा 2 अल्ट्रा और नोवा फ्लिप हैं, जिन्हें अलग-अलग तरह के यूज़र्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इन तीनों मॉडल्स के पीछे कंपनी का मूल विचार यह है कि प्रीमियम टेक्नोलॉजी न केवल लोगों की पहुंच में हो, बल्कि वह भरोसेमंद और व्यावहारिक भी हो.

> इस अवसर पर अपने विज़न को साझा करते हुए एआई स्मार्टफोन के सीईओ माधव शेठ ने कहा, एआई प्लस की शुरुआत इस विश्वास के साथ हुई थी कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारी सफलता ने यह साबित किया है कि यूज़र्स भरोसा और सरलता चाहते हैं. एक साल से भी कम समय में 10 लाख से अधिक यूज़र्स का जुड़ना हमारी इसी सोच की जीत है.'

हुंडई की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी जल्द हो सकती है लॉन्च

12 लाख रेंज में टाटा पंच ईवी को देगी टक्कर

यह मध्यम बजट के खरीददारों के लिए आकर्षक विकल्प बनेगी

नई दिल्ली, 12 अप्रैल भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी हुंडई मोटर कंपनी अपनी एक नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी को जल्द लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

हाल ही में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को भारी कैमोफ्लाज के साथ भारतीय सड़कों पर परीक्षण के दौरान देखा गया है, जिससे इसके जल्द बाजार में आने की अटकलें तेज हो गई हैं. यह नई इलेक्ट्रिक एसयूवी विशेष रूप से भारत के तेजी से बढ़ते कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है, जहां इसका सीधा मुकाबला टाटा पंच ईवी से माना जा रहा है. अनुमान है कि इसकी कीमत लगभग 11 लाख से 15 लाख (ऑन-रोड) के बीच रखी जा सकती है, जिससे यह मध्यम बजट के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकती है.

स्पाई तस्वीरों के अनुसार यह आने वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी बॉक्सी और मजबूत डिजाइन लैंग्वेज के साथ विकसित की गई है, जिसमें ऊंचा और दमदार एसयूवी स्टांस देखने को मिलता है. इसमें फ्लेयर्ड व्हील आर्च, आधुनिक पिक्सल-स्टाइल एलईडी हेडलैंप और टेललैंप, फ्लश फिटेड डोर हैंडल्स तथा रूफ रेल्स जैसे प्रीमियम डिजाइन एलिमेंट्स शामिल हैं.

> जानकारी के अनुसार इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में आधुनिक फीचर्स का लंबा सूचीपत्र देखने को मिल सकता है, जिसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, एम्बिएंट लाइटिंग और लेवल-2 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टमशामिल हो सकते हैं. इसके अलावा इसमें 30 किलोवाट और 40 किलोवाट क्षमता वाले दो बैटरी पैक मिलने की संभावना है, जो बेहतर ड्राइविंग रेंज और परफॉर्मेंस देने में सक्षम हो सकते हैं. यदि यह हुंडई इलेक्ट्रिक एसयूवी तय समय पर भारतीय बाजार में लॉन्च होती है, तो यह कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकती है.

वृहत आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी निवेशकों की नजर

मुंबई, 12 अप्रैल अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्ध विराम पर सहमति से घरेलू शेयर बाजारों बीते सप्ताह रही जबरदस्त तेजी के बाद आने वाले सप्ताह में निवेशकों को नजर वृहत आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी.

आने वाले सप्ताह में अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी शांति वार्ता की प्रगति बाजार को सबसे अधिक प्रभावित करेगी. साथ ही घरेलू स्तर पर खुदरा महंगाई, थोक महंगाई और आयात-निर्यात के आंकड़े भी जारी होने हैं जिनका बाजार पर बड़ा प्रभाव देखा

जायेगा. निवेशकों की नजर कंपनियों के तिमाही परिणामों पर भी रहेगी.

गत सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 4.230.70 अंक (5.77 प्रतिशत) की साप्ताहिक बढ़त में एक महीने के उच्चतम स्तर 77,550.25 अंक पर बंद हुआ. बाजार में गुरुवार को छोड़कर सभी चार दिन लिवाली का जोर रहा.नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक सप्ताह के दौरान 1,337.50 अंक यानी 5.89 फीसदी चढ़कर 24,050.60 अंक पर बंद हुआ. यह इसका भी एक महीने का उच्चतम स्तर है.

मझौली और छोटी कंपनियों में भी तेजी रही. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक में 7.74 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक में 7.60 प्रतिशत की साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गयी.

टीसीएस में वेतन वृद्धि की घोषणा

नई दिल्ली, 12 अप्रैल . देश की प्रमुख आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने अपने कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की घोषणा की है, जिसके तहत उच्च प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को दोहरे अंकों तक इंक्रीमेंट मिलेगा. यह वेतन संशोधन 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है और सभी पात्र कर्मचारियों पर लागू होगा. कंपनी ने यह निर्णय अपने मार्च तिमाही के वित्तीय परिणामों के साथ घोषित किया, जिसमें कहा गया कि मजबूत डील मोमेंटम और भविष्य की मांग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

सोने-चांदी में आई फिर तेजी

24 कैरेट गोल्ड 1 .52 लाख के पार

नई दिल्ली, 12 अप्रैल 2026 देश में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है, जिससे निवेशकों और ग्राहकों के बीच हलचल बढ़ गई है. बीते सप्ताह की शुरुआत में आई तेज गिरावट के बाद अब सोने के दाम लगातार दूसरे दिन बढ़े हैं.

ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर करीब 1,52,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है, जो बाजार में फिर से मजबूती के संकेत दे रही है. इसी तरह चांदी की कीमत भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है, जो लगभग 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही है.

विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों में यह उछाल वैश्विक बाजार में सुधार और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी का परिणाम है. खासतौर पर अमेरिका और ईरान के बीच जारी कूटनीतिक बातचीत ने बाजार के माहौल को प्रभावित किया है. भू-राजनीतिक तनाव के बीच निवेशक अक्सर सोने को सुरक्षित निवेश विकल्प मानते हैं, जिसके चलते इसकी मांग बढ़ जाती है और कीमतों में तेजी आती है.

समाचार विशेष

राज्यसभा चुनाव : 2 सीटों पर घमासान

रांची. झारखंड में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी है. राज्य से राज्यसभा की दो सीटें खाली होने जा रही हैं, जिन पर सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों की नजरें टिकी हुई हैं. इन सीटों को लेकर सत्ता पक्ष में भी अंदरूनी खींचतान के संकेत मिल रहे हैं, जबकि भाजपा सीमित संख्या के बावजूद मुकाबले को रोचक बनाने की रणनीति पर काम कर रही है.

सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत मान रहा है. पार्टी का मानना है कि राज्य की राजनीति में उसकी प्रमुख भूमिका के मद्देनजर उसे अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. हालांकि, यह राह इतनी आसान नहीं है. झामुमो को इन दोनों सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता होगी. गठबंधन की मजबूती और आपसी तालमेल इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएंगे. कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव कम अहम नहीं है. असम विधानसभा चुनाव में तालमेल की कमी के कारण पार्टी पहले से ही असहज स्थिति में है. ऐसे में झारखंड में राज्यसभा सीट पर अपनी दावेदारी छोड़ना उसके लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदायक साबित हो सकता है. पार्टी के भीतर यह संदेश देने की कोशिश होगी कि वह गठबंधन में बराबरी की हिस्सेदार है और अपने राजनीतिक हितों से समझौता नहीं करेगी.

भाजपा की मौजूदगी से रोमांचक होगा चुनाव-

विपक्षी भाजपा भी इस चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं दिख रही है. भले ही पार्टी के पास अपने दम पर जीत के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है, लेकिन सहयोगी दलों आजसू पार्टी, जदयू और लोजपा के साथ मिलाकर उसके पास 24 वोट हैं. ऐसे में यदि भाजपा चार अतिरिक्त वोटों का इंतजाम कर लेती है तो वह अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने की

आंकड़ा गठबंधन के पक्ष में

संख्या बल के लिहाज से देखें तो राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए एक उम्मीदवार को निर्धारित 28 वोटों की आवश्यकता होगी. सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों झामुमो, कांग्रेस, राजद, भाकपा माले को मिलाकर 56 विधायकों का आंकड़ा है, जो दो सीटों पर जीत के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसके लिए गठबंधन के घटक दलों में आपसी तालमेल और विश्वास आवश्यक है.

योगी-जयंत लिख सकते हैं नई पटकथा

मुजफ्फरनगर की रैली में साधेंगे जाट और गुर्जर वोट

लखनऊ. बीती 29 मार्च को नोएडा के दादरी में गुर्जरों का जमावड़ा और इसी दिन मेरठ में जाट राजा सूरजमल की प्रतिमा के अनावरण के बाद से पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लू चलने लगी है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दिए बयानों से भाजपा की जाट राजनीति में हलचल है. इसे लेकर पार्टी और गठबंधन के अंदर से कई विरोधी स्वर फूटे, जिसमें एक स्वर रालोद

अध्यक्ष जयन्त चौधरी का भी है. वहीं दोराहे पर खड़ी गुर्जर राजनीति अपना 'चौधरी' तलाश रही है.

इन्हीं चर्चाओं के बीच 13 अप्रैल को योगी और जयन्त मुजफ्फरनगर शहर में जनसभा कर नई पटकथा लिख सकते हैं. चुनावी वर्ष में भाजपा के कई जाट नेताओं की बेचैनी बढ़ी है. वहीं पार्टी गुर्जर जनप्रतिनिधियों से बात कर समाज का मलाल दूर करने के फार्मूले पर काम रही है. पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और गुर्जर दोनों सबसे प्रभावशाली राजनीतिक फैक्टर हैं. वर्ष 2014 के लोक सभा और 2017 में विधान सभा चुनाव के दौरान जाट और गुर्जर दोनों भाजपा के पक्ष में आए लेकिन 2019 के लोक सभा व 2022 के विधान सभा चुनाव में जाटों का बड़ा वोट रालोद के पास वापस जाता दिखाई पड़ा.

सस्ती राजनीति नहीं करने दूंगा

चौ. चरण सिंह के परिवार पर टिप्पणी करने वाले अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के संस्थापक अध्यक्ष रामावतार पलसानिया पर रालोद ने एफआइआर दर्ज करा दिया. जयन्त कह रहे हैं कि 'पहले भी यहां धार्मिक उन्माद बढ़ाकर राजनीति की गई. ऐसे कार्यक्रमों के जरिये जातीय उन्माद बढ़ाकर सस्ती राजनीति नहीं करने दूंगा'. भाजपा नेता गौरव चौधरी ने 'हमारा एक ही चौधरी और वो हैं जयन्त' कहकर अपनी ही पार्टी के चौधरियों को असमंजस में डाल दिया.

निशांत को लेकर अब भी सस्पेंस

पटना. नीतीश कुमार 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा. भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा पहले दिन से चल रही है. लेकिन उनको लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है.

इसका कारण यह है नीतीश अब भी कभी कभी निशांत की भूमिका लेकर संशय पैदा कर देते हैं तो कभी निशांत खुद भी पीछे हटते दिख रहे हैं. कहा जा रहा है कि नीतीश नहीं चाहते हैं कि निशांत को सीधे उप मुख्यमंत्री बनाया जाए. उन्होंने किसी को कहा कि अभी मंत्री बनाया जाए और कोई बहुत बड़ा मंत्रालय नहीं दिया जाए. दूसरी ओर निशांत ने कह दिया कि अभी नीतीश कुछ दिन और पद पर बने रहें तभी वे सरकार में कोई पद संभालने के लिए तैयार होंगे.

दूसरी ओर पार्टी इस मामले में बंटी दिख रही है. उप मुख्यमंत्री बनने की आस लगाए बैठे कई नेता चाहते हैं कि निशांत न बनें तो दो लोग उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे. क्योंकि अगर निशांत बनेंगे तो वे अकेले उप मुख्यमंत्री होंगे. दूसरी ओर नेताओं की बड़ी जमात जाहती है कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाए.

विशेष | **दीदी या दादा? नंदीग्राम से भवानीपुर तक महासंग्राम**

5 सीटें तय करेंगी सत्ता का भविष्य

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की गलियों में एक बार फिर चुनावी शंखनाद हो चुका है और इस बार की सियासी बिसात पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है. वैसे तो पूरे प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर घमासान है, लेकिन पांच ऐसी खास सीटें हैं जिन्होंने इस वक्त राजनीतिक पंडितों से लेकर आम जनता तक की धड़कनें तेज कर दी हैं. आज ममता बनर्जी भवानीपुर से नामांकन करेंगी.

नंदीग्राम की लाल माटी से लेकर कोलकाता के भवानीपुर की गलियों तक, यह लड़ाई सिर्फ जीत-हार की नहीं बल्कि वर्चस्व और पुरानी हार का बदला लेने की बन चुकी है. इन हॉट सीटों पर

होने वाला मुकाबला न केवल बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि जनता इस बार 'खेला' किसके साथ करने वाली है. ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक ने जहां टीएमसी की कमान संभाली है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत भाजपा के दिग्गज मंत्रियों ने भी मोर्चा खोल दिया है. बंगाल चुनाव की बात हो और नंदीग्राम का जिक्र न हो, ऐसा मुमकिन नहीं है. पिछली बार इसी सीट ने पूरे देश को चौंका दिया था, जब सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शिकस्त दी थी. इस बार भाजपा के लिए यह प्रतिष्ठा की सीट है और खुद अमित शाह सुवेंदु के नामांकन में ताकत झोंकने पहुंचे थे. दिलचस्प मोड़ यह है कि ममता बनर्जी इस बार भवानीपुर से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन उनके धुर विरोधी सुवेंदु अधिकारी वहां भी उनके सामने चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं.

त्रिकोणीय समीकरण की उलझन

मुर्शिदाबाद सीट पर इस बार मुकाबला काफी पेचीदा और त्रिकोणीय होता जा रहा है. यहां मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी-खासी तादाद है और कांग्रेस ने सिद्दीकी अली को उतारकर टीएमसी की राह मुश्किल कर दी है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर कांग्रेस मुस्लिम वोटों में सेंध लगाती है, तो इसका सीधा फायदा भाजपा के गौरी शंकर घोष को मिल सकता है. वहीं, जादवपुर जो कभी वामपंथ का अभेद्य किला हुआ करता था, वहां फिर से 'लाल झंडा' अपनी जमीन तलाश रहा है. टीएमसी के देबब्रत मजूमदार के सामने सीपीएम ने कोलकाता के पूर्व मेयर बिकास रंजन भट्टाचार्य को उतारा है.